

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 330
दिनांक 24 जून, 2019

तेल और गैस का उत्पादन

330. श्री पंकज चौधरी:

श्रीमती राम्या हरिदास:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए इसके आयात को कम करने के उद्देश्य से सरकार का देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने का वचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में नए तेल क्षेत्रों से तेल-उत्खनन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति में शीघ्रता लाने हेतु क्या ठोस उपाय कए गए हैं/कए जाने का वचार है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लए सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलें निम्नानुसार हैं:-

- i हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लए उत्पादन हिस्सेदारी सं वदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत रियायतों, अव ध बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लए नीति।
- ii खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति।
- iii हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस संग नीति।
- iv उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की अव ध बढ़ाने के लए नीति।
- v कोल बैड मथेन सीबीएम से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लए नीति।
- vi नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना।
- vii तलछटीय बे सन में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन। शेल गैस नीति आदि।
- viii हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनः आकलन।
- ix एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लए नीतिगत ढांचा।

- x तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नीति।
- xi मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संवदाओं, कोल बेड मथेन संवदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा।

सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसनों के गैर-अन्वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और वदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और संवदागत शर्तों को सरल बनाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी 2 और 3 के तलछटीय बेसनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली, राजकोषीय प्रोत्साहन देकर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, वपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पूंजी को शामिल करना, नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों के लिए सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्यादा आजादी देना, अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना तथा इलेक्ट्रॉनिक एकल खड़की व्यवस्था सहित कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना है।

(ग) पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के रूप में घरों, वाणिज्यिक इकाइयों और उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में वाहनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अब तक पीएनजीआरबी ने 10वें सीजीडी बोली दौर तक पूरे देश में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु 228 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को प्राधिकृत किया है। पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए 9वें और 10वें सीजीडी बोली दौर के तहत 298 जिलों को कवर किया गया है।
